डाक पंजीयन क्र. L/ RNP/म.प्र./ मन्दसौर/122/ 2024- 26
ई-पेपर www.guruexpress.live

बात आपकी, शब्द हमारे

गुरु एक्सप्रेस

सुबह का अखबार

संपादक – आशुतोष नवाल

वर्ष 18 | अंक 111 | पृष्ठ 4 | मन्दसौर | गुरुवार 01 फरवरी 2024 | मूल्य 2 रुपया

युवक ने फांसी लगाई, मौत

नीमच, 31 जनवरी गुरु एक्सप्रेस। जिले के जावद थाना क्षेत्र में आने वाले गांव बांगरेड़ में मंगलवार रात अज्ञात कारणों के चलते एक 22 वर्षीय युवक ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

दरअसल, बांगरेड़ निवासी युवक शुभम पिता किशनलाल बंजारा उम्र 22 वर्ष ने मंगलवार रात्रि में अपने घर में आई वी सेट(ड्रिप की नली) से फांसी का फंदा बनाकर मौत को गले लगा लिया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने उसे तत्काल नीमच के बड़े अस्पताल लेकर पहुंचे। मगर यहां डॉक्टर ने उसे अमृत घोषित कर दिया। वहीं बुधवार को युवक के शव का परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमॉर्टम किया गया। पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर आत्महत्या के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

फर्जीवाड़ा: कबाड़ के पार्ट्स से असेंबल होती बसें

एक ही नंबर और परमिट पर दौड़ रही दो-दो बसें

मंदसौर, 31 जनवरी गुरु एक्सप्रेस। एक माह पहले गुना में हुए हादसे में तेरह लोगों की बस में जिंदा जलने से मौत हो गई। इसके बाद जिला परिवहन विभाग सड़क पर उतरा। थोड़े दिन कार्रवाई के बाद फिर स्थिति जस की तस हो गई है। इधर गुना मे जिस बस में हादसा हुआ उसका नंबर फर्जी था। नंबर प्लेट, परमिट और फिटनेस में भी बड़ा खेल किया गया था। मंदसौर जिले से गुजर रही या मंदसौर जिले में चल रही बसों में भी तगड़ा खेल किया गया है। कबाड़ के पार्ट्स से असेंबल एक ही नंबर और परमिट की बसें जिले की सड़को से गुजर रही है। चंद रुपए बचाने के लिए बस मालिक नियमों की अनदेखी करते हैं। एक ही नंबर और परमिट पर दो-दो बसें दौड़ाते रहते हैं। कबाड़ से पार्ट्स लेकर बसें असेंबल की जाती हैं। इसकी जानकारी भी परिवहन विभाग को नहीं दी जाती। कुछ बस चालकों से इस पूरे खेल के बारे में चर्चा में बहुत कुछ सामने आया।

यह है बस बनने और रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस...

चेसिस किसी भी चार पहिया वाहन का आधार होता है, जिस पर पूरा ढांचा खड़ा होता है। बस मालिकों को वाहन कंपनी से चेसिस ही मिलता है। अलग-अलग सिटिंग कैपेसिटी के हिसाब से चेसिस होता है। इसे एक नंबर भी दिया जाता है। इसके बाद बस ऑपरेटर अपने हिसाब से उस पर बॉडी बनवाते हैं। बॉडी बनाने वाली कंपनियां भी रजिस्टर्ड होती हैं। नियमानुसार तैयार बस को रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस ले जाया जाता है। रजिस्ट्रेशन के पेपर्स में बस का इंजन नंबर, चेसिस नंबर, मॉडल नंबर, रजिस्ट्रेशन तारीख, कलर, सिटिंग कैपेसिटी, व्हील बेस, मालिकाना हक, बीमा और रजिस्ट्रेशन की वैलेडिटी समेत अन्य जानकारियां दर्ज की जाती हैं। इसके बाद ही गाड़ी रोड़ पर आती है।

इसके बाद ऐसे होता है खेल...

पहला - बस मालिक के पास कई गाड़ियां होती हैं। होता यूं है कि कोई नई गाड़ी एक्सीडेंट में डैमेज हो गई। उसमें से अच्छे पार्ट्स निकलवाकर दूसरी पुरानी गाड़ियों में लगवा देते हैं। जबकि, उसके आरटीओ नंबर पर पुरानी गाड़ी चलाते हैं। किसी गाड़ी का चेसिस या दूसरा पार्ट खराब हो गया हो, पुराना या टूट-फूट गया हो, तो कई बार बस ऑपरेटर या तो नया चेसिस खरीदते हैं या कबाड़ से ले लेते हैं। उस पर पुरानी बस की बॉडी लगवा लेते हैं। नियमानुसार यदि बस का चेसिस बदला जाता है, तो आरटीओ को जानकारी देना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन में भी अपडेट कराना होता है, लेकिन पैसे बचाने के लिए अधिकांश बस ऑपरेटर ऐसा नहीं करते।

दूसरा- जुगाड़ से बनवा लेते हैं पूरी बस...

खेल करने वाले बस ऑपरेटर पूरी बस ही जुगाड़ से बनवा लेते हैं। जैसे- इंजन कहीं से खरीद लिया, चेसिस कबाड़ से ले लिया। इसी तरह, अन्य पार्ट्स भी जुगाड़ कर बस तैयार करवा ली। बस का रजिस्ट्रेशन कराने की जगह किसी दूसरी बस की नंबर प्लेट इस पर लगा देते हैं। ऐसे में आरटीओ के पास यह जानकारी ही नहीं होती कि ये कौनसी बस है। वह बस नंबर प्लेट ही देखते हैं। उसी हिसाब से दस्तावेज देख लेते हैं।

तीसरा- एक ही नंबर और परमिट पर दो गाड़ियां..

कई बस ऑपरेटर एक ही नंबर और परमिट पर दो गाड़ियों चलाते हैं। कई गाड़ियों से आरटीओ रजिस्ट्रेशन में लिखे चेसिस नंबर, इंजन नंबर इसलिए नहीं मिलते, क्योंकि गाड़ी ही दूसरी होती है। जैसे- एक बस का आरटीओ नंबर दूसरे की बस पर लगाकर चलाओ। कई लोग तो परमिट भी जालसाजी से बनवा लेते हैं। अगर नियमानुसार गाडी की जांच की जाए, तभी फर्जीवाड़ा पकड़ में आता है।

चेसिस, इंजन का फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं...

जब आरटीओ अमला या पुलिस बस को चेकिंग के लिए रोकते हैं, तो वह दस्तावेज ही चेक करते हैं। नंबर प्लेट देखकर दस्तावेज चेक होते हैं। चेसिस, इंजन का फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करते। यानि अमला दस्तावेजों में तो चेसिस नंबर, इंजन नंबर देख लेता है, लेकिन गाडी में वही चेसिस और इंजन लगे हैं, इसकी जांच नहीं होती। इसी का फायदा बस ऑपरेटर उठाते हैं।

अभी भी 40 फीसदी वाहनों में नहीं लगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, शुरु होगी चलानी कार्यवाही

मंदसौर, 31 जनवरी गुरु एक्सप्रेस। हाई कोर्ट के सख्त आदेश के अनुसार राज्य में चलने वाले वाहनों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिया गया है। प्रशासन और ट्रैफिक विभाग इसपर लगातार कार्रवाई की जा रही है। बावजूद इसके अभी तक 60 लाख वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लग पाई है। जिसके चलते पुलिस मुख्यालय ने चालानी कार्रवाई तेज करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। बता दे कि जिले में 40 फीसदी वाहनों में अभी भी हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है। प्रदेश भर में यही स्थिति है।

राज्य में 1 करोड़ 74 लाख वाहन...

बता दें कि मध्य प्रदेश में 1 करोड 74 लाख वाहन हैं। हाई कोर्ट की सख्ती के कारण परिवहन विभाग और पुलिस के आला अधिकारियों की चिंता बढ गई है। बता दें कि, हाई कोर्ट ने 15 जनवरी तक सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के साथ चार पहिया वाहन चालक और सवारी के लिए सीट बेल्ट और दोपहिया वाहन चालक और सवारी के लिए हेलमेट लगाने का 100 फीसदी पालन कराने के लिए परिवहन विभाग को निर्देशित किया था। लेकिन, अभी तीनों प्रकार के नियमों पर पूरी तरह से अमल नहीं हो रहा है।

इनका कहना...

15 जनवरी तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाकर देना थी। पेंडेंसी वाली फाइलों को लगातार निपटा रहे हैं। जिले में चेकपाइंट भी बनाए जाएंगे, ताकि वाहनों का डिटेल मौके पर ही मिल सके। इसी आधार पर कार्रवाई होगी। फिलहाल तारीख बढ़ने को लेकर कोई निर्देश नहीं मिले हैं। प्रक्रिया का पालन होगा।

वीरेंद्रकुमार यादव
एआरटीओ, मंदसौर

स्मार्ट मीटर लगाने की गति धीमी

फरवरी की बजाय 31 मार्च तक लग सकते है...

मंदसौर, 31 जनवरी गुरु एक्सप्रेस। इस साल फरवरी के अंत तक स्मार्ट मीटर लगाने का पहले चरण पूरा करने का टारगेट था। इस दौरान कंपनी को शहर में 20 हजार स्मार्ट मीटर लगाना है। हालांकि, काम की गति धीमी होने के कारण मार्च में ये टारगेट पूरा हो सकेगा। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा मंदसौर शहर में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य किया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के पहले चरण में शहर के अलग-अलग इलाकों में 20 हजार स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य किया जा रहा है। बता दें कि पहले चरण में उन इलाकों का चयन किया गया है, जहां लाइन लास का प्रतिशत अधिक है, यानी बिजली चोरी और अन्य मामलों में बिजली कंपनी को ज्यादा नुकसान हो रहा है।

अभी तक लग चुके हैं 6 हजार 900 स्मार्ट मीटर...

पहले चरण में फरवरी तक 20 हजार स्मार्ट मीटर लगाने का टारगेट सेट किया गया है। काम धीमी गति से चलने के कारण मार्च में जाकर काम पूरा हो सकेगा। बता दें कि, शहर में घरेलू, व्यवसाइक, ओद्योगिक समेत सभी श्रेणियों में लगे कुल मीटरों की संख्या 35 हजार है, जिन्हें कंपनी द्वारा स्मार्ट मीटर में बदला जा रहा है। बैंगलुरु की बीसीआइटीएस कंपनी द्वारा शहर में सभी फीडरों का सर्वे करके दिसंबर से स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरु किया गया है। अब तक 6 हजार 900 स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। दूसरे चरण में 9 फीडर में करीब 15 हजार मीटर स्मार्ट किये जाएंगे। विद्युत वितरण कंपनी हर घर में उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर दे रही है।

दूसरे चरण ने 9 फीडर क्षेत्र में लगेंगे नए मीटर...

विद्युत वितरण कंपनी के अफसरों का कहना है कि शहर में कुल 2 चरणों में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य पूरा होगा। पहले चरण में 12 और दूसरे चरण में 9 फीडर क्षेत्र इसमें शामिल किए गए हैं। दूसरे चरण का सर्वे पूरा होते ही पूरे शहर में मीटर स्मार्ट लगाए जाएंगे। मंदसौर शहर में ये कार्य पूरा होने के बाद सुवासरा में स्मार्ट मीटर के लिए सर्वे शुरु होगा।

हाईकोर्ट ने कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार को लगाई लताड़

एक लाख का जुर्माना लगाया, कहा-अदालत में आकर माफी मांगे

मंदसौर, 31 जनवरी गुरु एक्सप्रेस। हाईकोर्ट ने मंदसौर कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार को जमकर लताड़ लगाई है। एक मामले में 13 साल से लापरवाही बरती जा रही थी। सिविल कोर्ट के निर्णय के बाद भी आदेश का पालन नही किया गया। जबकि, इसकी शिकायत मुख्यमंत्री तक की गई। इसके बाद भी प्रशासन कोर्ट का आदेश मानने को तैयार नहीं था। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा। यहां हाईकोर्ट ने कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार को जमकर लताड लगाई। वहीं एक लाख का जुर्माना और अदालत में आकर माफी मांगने का आदेश दिया है।

अभिभाषक मुकेश माली ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुल्तानपुरा स्थित चारभुजानाथ मंदिर है। जिसको प्रशासन अपना बता रहा था। मामला सिविल कोर्ट में गया। जिसके बाद कोर्ट ने इसे प्रशासन का मंदिर नहीं मानते हुए निजी बताया। इस संबंध मे आदेश भी जारी कर फरियादी के पक्ष में फैसला सुनाया। यह फैसला 2011 में कोर्ट ने सुनाया। इसके बाद कितने ही कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार आए, लेकिन किसी ने कोर्ट के आदेश को नहीं माना। इस मामले में कोर्ट ने कंटेंप्ट भी लिखा। अभिभाषक मुकेश माली ने बताया की हमने सीएम हेल्प लाईन से लेकर सीएम सहित कई अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया। इसके बाद भी प्रशासन इस मामले में कोर्ट के आदेश का पालन नही कर रहा था। इसके बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। यहां हाईकोर्ट ने फरियादी पक्ष को सुना। न्यायाधीश विवेक रुसिया की अदालत ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने इतने सालों तक कोर्ट का आदेश नहीं मानने का कारण प्रशासन के वकील से पूछा। कोर्ट ने सख्त लहजा अपनाते हुए कलेक्टर, तहसीलदार और एसडीएम पर एक लाख का जुर्माना लगाया। वहीं कोर्ट में पेश होकर माफी मांगने के आदेश दिए। इस मामले में फरियादी पक्ष को न्याय दिलाने में अभिभाषक मुकेश माली की भूमिका महत्वपूर्ण रही।

एक समय मंदसौर लोकसभा क्षेत्र ने एक साथ दिए थे चार सांसद

मंदसौर, 31 जनवरी गुरु एक्सप्रेस। एक समय मंदसौर लोकसभा क्षेत्र इसलिए भी विख्यात रहा है, जहां से एक साथ चार सांसद थे। तीन ने लोकसभा और एक ने राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किया। इनमें से भी दो केंद्रीय मंत्री थे। यह गौरव मिला 1999 से 2004 के दौरान। भाजपा के डॉ. लक्ष्मीनारायण पांडे, सुंदरलाल पटवा और सत्यनारायण जटिया लोकसभा में थे तो कांग्रेस के बालकवि बैरागी राज्यसभा में। जावरा के रहने वाले पांडे मंदसौर से, कुकडेश्वर निवासी सुंदरलाल पटवा होशंगाबाद से और जावद के मूल निवासी सत्यनारायण जटिया उज्जैन से निर्वाचित हुए थे। तीनों का जन्म स्थान मंदसौर लोकसभा क्षेत्र ही रहा है। चौथे सांसद के रूप में राज्यसभा पहुंचे बैरागी मनासा के रहने वाले थे।

वाराणसी ज्ञानवापी केस में अब तक का सबसे बड़ा फैसला...

हिंदू पक्ष को व्यास तहखाने में मिला पूजा का अधिकार

वाराणसी, 31 जनवरी। ज्ञानवापी केस में वाराणसी की जिला अदालत ने अब तक का सबसे बडा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा पाठ का आदेश दिया है। जिला प्रशासन को 7 दिन के अंदर यहां पूजा पाठ की व्यवस्था करने का आदेश दिया है।

ज्ञानवापी परिसर में दो तहखाने हैं। इसी के उत्तर ज्ञानवापी मस्जिद बनी है। एक तहखाना हिंदू पक्ष के पास था, जहां 1993 तक पूजा होती थी। लेकिन तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार ने यहां पूजा बंद करवा दी। अब हिंदू पक्ष ने याचिका दायर कर मांग की है कि यहां पूजा की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने एक दिन पहले सुनवाई पूरी करते हुए व्यास तहखाना कलेक्टर के सुपुर्द करने को कहा था। आज पूजा की अनुमति भी दे दी। कोर्ट के आदेश के मुताबिक यहां नियमित पूजा होगी। मुस्लिम पक्ष इस फैसले के खिलाफ उत्तरी अदालत का दरवाजा खटखटाएगा।

जानें क्या है व्यास तहखाना

ज्ञानवापी परिसर में नंदी भगवान के ठीक सामने व्यास परिवार का तहखाना है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन के मुताबिक, साल 1993 तक यहां पूजा होती थी, लेकिन नवंबर 1993 में अवैधानिक रूप में मुलायम सरकार की ओर से यहां पूजा पर पाबंदी लगा दी गई थी।

जावरा में सोया प्लांट पर ईडी का छापा

अंबिका साल्वेक्स की वर्द्धमान साल्वेंट इंडस्ट्रीज पर सर्चिंग, कर्मचारियों को किया बाहर

जावरा, 31 जनवरी गुरु एक्सप्रेस। शहर में स्थित सोया प्लांट पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को छापा मारा। सुबह इंदौर से टीम यहां पहुंची। टीम जावरा स्थित अंबिका सॉल्वेक्स के सोया प्लांट इंडस्ट्रीज में सर्चिंग कर रही है। इस दौरान कंपनी के सभी कर्मचारियों को बाहर कर दिया गया है। सभी के मोबाइल भी बंद करा दिए गए हैं।

जावरा स्थित अंबिका सॉल्वेक्स के सोया प्लांट वर्धमान सॉल्वेंट इंडस्ट्रीज में कार्रवाई चल रही है। हालांकि कारण अभी तक सामने नहीं आया है। न हीं कोई जांच अधिकारी इस संबंध में बात करने के लिए तैयार है। फैक्ट्री का गेट लगा दिया है। किसी को अंदर-बाहर नहीं आने दिया जा रहा। बताया जा रहा है कि टीम के अधिकारियों ने फैक्ट्री के कुछ ट्रकों की चाबियां भी अपने पास रख ली है। दोपहर 2.30 बजे प्लांट का बॉयलर बंद करवा दिया। कुछ श्रमिक थे, उन्हें भी बाहर कर दिया। देर रात खबर लिखे जाने तक ईडी टीम की सर्चिंग जारी थी।

टीम में 8 से 10 सदस्य शामिल...

बताया जा रहा है कि इंदौर से 3 वाहनों में सवार होकर ईडी टीम के 8 से 10 सदस्य आए है। फैक्ट्री परिसर में इंदौर, गुजरात पासिंग नंबर की गाडियां खडी है। कुछ गाडियो का अंदर से बाहर आना-जाना लगा है। कंपनी के गेट पर निजी सुरक्षा गार्ड खडे है। वह कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा।

पहले भी हो चुकी कार्रवाई...

अंबिका साल्वेक्स के इस प्लांट में पूर्व में भी आयकर, जीएसटी की कार्रवाई हो चुकी है। इस कंपनी के इंदौर, नीमच सहित अन्य स्थानों पर भी प्लांट बताए जा रहे है। संभवत: रतलाम जिले में पहली बार ईडी की कार्रवाई हो रही है। कुछ अधिकारियों से जानकारी भी लेना चाही, लेकिन बोलने के लिए कोई तैयार नहीं थे।

कार से मिला पौन क्विंटल डोडाचूरा, एक गिरफ्तार

शामगढ़, 31 जनवरी गुरु एक्सप्रेस। पुलिस ने एक स्विफ्ट कार से 74 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा बरामद किया है। मामले में कार चालक को गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपियों के संबंध में पुलिस पूछताछ कर रही है।

शामगढ थाना पुलिस ने बताया की मुखबीर से सूचना मिली थी कि एक कार से बडी मात्रा में हरिपुरा-देवरी मार्ग पर अवैध डोडाचूरा तस्करी कर ले जाया जा रहा है। जिसके बाद पुलिस ने एक टीम का गठन कर मौके पर रवाना की।पुलिस ने थाना क्षेत्र के शामगढ हरिपुरा रोड, देवरी तिराहा के निकट नाकाबंदी कर मुखबीर द्वारा बताए हुलिए वाली स्विफ्ट कार को रोककर चालक को हिरासत में लिया। कार की तलाशी लेने पर डिक्की में रखे चार प्लास्टिक के कट्टो में भरा 72 किलोग्राम डोडाचूरा बरामद किया गया। जिसकी कीमत 1 लाख 44 हजार रुपए आंकी जा रही है। मौके से गिरफ्तार आरोपी ने पुलिस की पूछताछ में अपना नाम हुकुम सिंह पिता राजेंद्र सिंह राजपूत उम्र 20 वर्ष निवासी सुराखेडी थाना गरोठ जिला मंदसौर का होना बताया।आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 के तहत अपराध दर्ज किया है। आरोपी डोडाचूरा कहां से लेकर आया था और कहां ले जा रहा था। इस मामले में आरोपी से पूछताछ की जा रही है।

नगरपालिका ने 79 करोड़ के 14 कार्यों के लिए सिंहस्थ मद से की मांग

मंदसौर, 31 जनवरी गुरु एक्सप्रेस। प्रदेश में नई सरकार के गठन के साथ ही नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति काफी खराब चल रही है। लेकिन, मंदसौर नगरपालिका द्वारा सिंहस्थ मद से शहर को संवारने का प्रयास किया जा रहा है। नपा ने पशुपतिनाथ मंदिर व शिवना नदी से जुडे अधिकांश विकास के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से सिंहस्थ 2028 की मद से राशि मांगी है। नगर पालिका ने 79 करोड 25 लाख के 14 कामों की सूची तैयार कर भेजी है।

इसमें मुख्य रूप से पशुपतिनाथ लोक से लेकर शिवना नदी के घाट सौंदर्यीकरण से लेकर पुलिया व चौराहों के सौंदर्यीकरण के साथ सडक व डिवाईडर के निर्माण सहित आम लोगों की सुविधा से जुडे विकास के बडे मुद्दों को शामिल किया है। शासन को भेजी सूची में सभी कामों को उच्च प्राथमिकता में लेते हुए हर एक प्रोजेक्ट का शहर के लिए महत्व भी बताया है। आने वाले चार सालों में शहर विकास से जुडे बडे प्रोजेक्ट सिंहस्थ मद में शामिल कर नपा ने विकास के बडे प्रोजेक्ट व बडी राशि मंजूर कराने की पहल की है।

बताते नगर पालिका ने सिंहस्थ को देखते हुए जो प्रोजेक्ट तैयार करते हुए राशि की मांग की है, उनमें पशुपतिनाथ मंदिर से लेकर शिवना नदी व घाटों से लेकर आवागमन एवम पार्किंग व पुलिया का निर्माण अहम रखा है। शहर से गुजर रही शिवना नदी के तट पर विश्वप्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ की दुर्लभ व इकलौती प्रतिमा है, जहां पशुपतिनाथ लोक का निर्माण भी हो रहा है। ऐसे में उज्जैन आने वाले भक्त यहां भी दर्शन करने पहुंचते है। इसी कारण नदी व घाटों के अलावा पार्किंग से लेकर डिवाईडर, चौराहें सहित आवागमन व जनसुविधा व आस्था को देखते हुए प्रोजेक्ट तैयार करते हुए राशि की मांग की है।

इन कामों के लिए मांगा बजट...

- शिवना नदी के तटों का सौंदर्यीकरण के लिए 15 करोड़। पशुपतिनाथ लोक परिसर के दूसरे चरण के लिए 25 करोड़।
- डिवाईडर व सौंदर्गीकरण के लिए 4 करोड़।
- रोड स्वीपिंग मशीन के लिए 1 करोड़।
- हाईमास्ट मय सोलर लाईट के लिए 2.10 करोड़।
- चौराहों व पार्क सौंदर्गीकरण के लिए 5 करोड़।
- प्रवेश द्वार के लिए 2.50 करोड़।
- जलकुंभी क्लीनिंग मशीन के लिए 1.15 करोड़।
- रामानुज कोट परिसर के समीप पार्किंग व फुटओवरब्रिज निर्माण के लिए 2.5 करोड़।
- शिवना की छोटी पुलिया पर नया पुल निर्माण के लिए 8. 75 करोड़।
- 2.15 करोड शिवना नदी के तट पर रिंग रोड के मुक्तिधाम तक बढ़ाने के लिए
- काश्तकार होटल से नीचे शिवना नदी पर सीतामऊकी ओर पुलिया एवं स्टाप डेम का निर्माण के लिए 6. 5 करोड़
- लक्कड पीठा पंप हाउस परिसर के समीप पार्किंग व फुटओवर बिज निर्माण के लिए 2 करोड़।
- काश्तकार होटल से शिवना छोटी पुलिया तक डामरीकरण के लिए 1 करोड़ रुपए।

विचार-मंथन

सरकारी इच्छाशक्ति का अभाव...

बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में देरी कोई नई बात नहीं है। हालांकि इस समस्या से पार पाने के लिए समय-समय पर सख्ती बरतने का प्रयास होता रहा है, मगर अब तक उल्लेखनीय नतीजे नहीं निकल पाए हैं। यही वजह है कि विलंब से चल रही परियोजनाओं की लागत बढ़ जाती है, जिसका बोझ सार्वजनिक खजाने पर पड़ता है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक डेढ़ सौ करोड़ रुपये से अधिक खर्च वाली चार सौ इकतीस बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की लागत 4.82 लाख करोड़ रुपए से अधिक बढ़ गई है। मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बीते दिसंबर तक एक हजार आठ सौ बीस ऐसी परियोजनाएं देर से चल रही थीं, जिनमें से चार सौ बत्तीस परियोजनाओं की लागत बढ़ गई है। ये परियोजनाएं औसतन तीन वर्ष से अधिक की देरी से चल रही हैं। इसके प्रमुख कारणों में भूमि अधिग्रहण में विलंब, पर्यावरण और वन विभाग से मंजूरी मिलने में देरी और बुनियादी संरचना में कमी को बताया गया है। इसके अलावा परियोजना का वित्तपोषण, विस्तृत अभियांत्रिकी को मूर्त रूप देने में देरी, परियोजनाओं की संभावना में बदलाव, निविदा प्रक्रिया और ठेके देने में देरी, उपकरण मंगाने में विलंब, अप्रत्याशित भू-उपयोग में परिवर्तन आदि भी बड़े कारण हैं। ये सारी वजहें पहले भी बताई जाती रही हैं। इससे निपटने के लिए परियोजना में देरी होने पर ठेकेदार से प्रतिदिन के हिसाब से विलंब शुल्क वसूलने का प्रावधान किया गया। तब माना गया कि इससे परियोजनाएं समय पर पूरी हो सकेंगी और उन पर लागत बढ़ने के खर्च से बचा जा सकेगा। मगर अब भी चार सौ से ऊपर परियोजनाएं अगर तीन वर्ष की औसत देरी से चल रही हैं, तो जाहिर है कि परियोजनाओं को मंजूरी देने से पहले उनके व्यावहारिक पहलुओं का मूल्यांकन ठीक से नहीं किया जाता। आमतौर पर सड़कों, पुलों आदि जैसी बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं का निर्णय राजनीतिक स्तर पर ले लिए जाते हैं। उनके मूल्यांकन में प्रायः संभावित अड़चनों, मसलन भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण संबंधी मानक, भू-उपयोग आदि को लेकर लापरवाही बरती जाती है। बिना जरूरी मंजूरी के परियोजनाओं के ठेके इस विश्वास के साथ दे दिए जाते हैं कि उन अड़चनों से पार पा लिया जाएगा। इसका नतीजा यह होता है कि कहीं अगर परियोजना के बीच में आने वाले किसी छोटे से हिस्से पर भी किसी ने मुकदमा कर दिया, तो वह तब तक लटक जाती है, जब तक न्यायालय का निर्णय नहीं आ जाता। मुआवजे आदि को लेकर भी विवाद पैदा हो जाते हैं। यह भी छिपी बात नहीं है कि बुनियादी ढांचा क्षेत्र की परियोजनाओं में देरी और फिर उनकी लागत बढ़ने के पीछे बड़ा कारण भ्रष्टाचार है। ठेकेदार और वित्तपोषण करने वाले विभाग के बीच अक्सर भुगतान को लेकर रस्साकशी देखी जाती है। समय पर भुगतान न मिल पाने से ठेकेदार काम बीच में छोड़ देते हैं। भुगतान समय पर न मिलने के पीछे अक्सर कमीशनखोरी बड़ा कारण होती है।इस पर अनेक निर्माण कंपनियां सार्वजनिक रूप से असंतोष प्रकट कर चुकी हैं। परियोजना में विलंब होने का अर्थ है कि उसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री और सेवाओं की कीमत बढ़ती जाती है। कई बार सक्षम ठेकेदारों को काम न दिए जाने की वजह से भी उनमें जिस ढंग की अभियांत्रिकी का उपयोग अपेक्षित होता है, वह नहीं हो पाता। ये सारे तथ्य किसी से छिपे नहीं हैं, मगर इनमें सुधार के व्यावहारिक उपाय नहीं किए जाते तो जाहिर है, परियोजनाओं को समय पर पूरा कराने की इच्छाशक्ति का अभाव है।

गठबंधन बिखरने का जिम्मेदार कौन?

अजीत द्विवेदी

बड़ा सवाल यह है कि गठबंधन की केंद्रीय पार्टी के तौर पर क्या कांग्रेस को पहल अपने हाथ में नहीं रखनी चाहिए थी? उसने क्यों गठबंधन की जिम्मेदारी आउटसोर्स की थी? पहले शरद पवार गठबंधन बनाने की कोशिश करते रहे। फिर ममता बनर्जी और के चंद्रशेखर राव ने इसका प्रयास किया। अरविंद केजरीवाल ने भी एक समय इसकी कोशिश की और अंत में नीतीश कुमार ने सफल प्रयास किया। नीतीश पिछले साल अप्रैल में इस सिलसिले में पहली बार मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिले थे। तब तक खबर थी कि राहुल के मन में नीतीश को लेकर नाराजगी है क्योंकि 2015 में गठबंधन के साथ लड़ने के बाद वे राजद और कांग्रेस को छोड़ कर भाजपा में चले गए थे। अब भी यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस को नीतीश पर पहले से भरोसा नहीं था। खड़गे ने तो यहां तक कि उनको पहले ही पता चल गया था कि नीतीश गठबंधन छोड़ेंगे। अब सवाल है कि जब पहले ही पता चल गया था या भरोसा नहीं था तो उनको साथ बैठा कर बात करने का क्या मतलब था? नीतीश कुमार जब गठबंधन का प्रस्ताव लेकर दिल्ली पहुंचे थे और खड़गे व राहुल से मिले थे तब दोनों ने उनके प्रयास का समर्थन किया था। कांग्रेस ने न सिर्फ उनके प्रयास का समर्थन किया, बल्कि उनके तय किए गए राजनीतिक एजेंडे को अपनाया था। जाति गणना और आरक्षण की सीमा बढ़ाना नीतीश कुमार का आइडिया था, जिस पर राहुल गांधी कर्नाटक का विधानसभा चुनाव लड़े। उन्होंने नीतीश के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए प्रेस कांफ्रेंस में पूछना शुरू किया कि इसमें कितने ओबीसी हैं या यह बताना शुरू किया कि देश के 90 सचिवों में सिर्फ तीन सचिव ओबीसी हैं या यह नारा दिया कि 'जितनी आबादी उतना हक'। सोचें, जब नीतीश पर भरोसा नहीं था तब तो उनको गठबंधन बनाने की जिम्मेदारी दी गई, उनके राजनीतिक एजेंडे को चुनावी मुद्दा बनाया गया और उनकी पहल पर पटना में पहली बैठक हुई। इसका मतलब है कि भरोसा नहीं होने वाली बात बाद में जोड़ी गई है।बड़े और गठबंधन की केंद्रीय पार्टी होने के नाते यह कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती थी कि वह सभी पार्टियों को वैचारिक और राजनीतिक रूप से बांध कर रखे। इसके लिए जरूरी था कि पहली या दूसरी बैठक में ही संगठन का ढांचा बनता, संयोजक व अध्यक्ष नियुक्त किए जाते, न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय होता और सबसे जरूरी सीटों का बंटवारा होता। ध्यान रहे नीतीश कुमार और ममता बनर्जी दोनों ने एक सितंबर को मुंबई में हुई बैठक में सीट बंटवारे पर जोर दिया था और 31 अक्टूबर तक की अघोषित समयसीमा भी तय की गई थी। नीतीश ने बैठक में कहा था कि गठबंधन में सबसे पेचीदा मामला सीट बंटवारे का है इसलिए पहले उसे निपटाया जाए। लेकिन कांग्रेस ने इस पर चुप्पी साध ली। कांग्रेस की रणनीति यह थी कि साल के अंत में होने वाले पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव तक इसे टाला जाए क्योंकि उसमें कांग्रेस को अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद थी। अगर वह तीन राज्यों में सरकार बना लेती तो मोलभाव की क्षमता बढ़ जाती। तब वह ज्यादा मजबूती से सीटों के लिए मोलभाव करती। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कांग्रेस सिर्फ एक राज्य में जीत पाई। जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आने लगे तब कांग्रेस के हाथ पैर फूले और सारे नतीजे आने से पहले ही कांग्रेस ने विपक्षी पार्टियों को बैठक का न्योता भेजना शुरू कर दिया, जिसे सबने ठुकरा दिया। जाहिर है सबने कांग्रेस की होशियारी भांप ली थी। इसलिए बाद में बैठक के लिए 19 दिसंबर की तारीख तय हुई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ममता बनर्जी ने अकेले लड़ने का मन बना लिया था तो नीतीश कुमार ने गठबंधन बदलने का फैसला कर लिया था। यह सबको पता है कि ज्यादातर प्रादेशिक पार्टियों के नेता इस उम्मीद में गठबंधन से जुड़े थे कि सब मिल कर लड़ेंगे तो भाजपा की सीटें कम कर देंगे और तब इधर या उधर के गठबंधन में बड़ी भूमिका मिल सकता है। त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति में सर्वोच्च पद मिलने की भी उम्मीद कई नेता लगाए हुए थे। लेकिन हिंदी पट्टी के तीन राज्यों में भाजपा की जीत और कांग्रेस की हार ने उनका मनोबल तोड़ दिया। पहले गठबंधन फाइनल करने और सीट बंटवारे में हुई देरी से निराशा था और ऊपर से दिसंबर के पहले हफ्ते में आए चुनाव नतीजे ने नेताओं को और निराश किया। भाजपा को टक्कर देने की उम्मीद टूटी तो सब अपने अपने रास्ते तलाशने लगे। इसलिए किसी एक नेता या एक पार्टी को जिम्मेदार ठहरा कर उसके ऊपर ठीकरा फोड़ने से किसी को कुछ हासिल नहीं होने वाला है।

कलेक्टर ने ग्राम पंचायत सांडिया एवं फूलपुरा में विकास एवं निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया

नीमच, 31 जनवरी गुरु एक्सप्रेस। कलेक्टर श्री दिनेश जैन ने बुधवार को नीमच जिले की मनासा जनपद की ग्राम पंचायत सांडिया और फूलपुरा का भ्रमण कर, ग्राम पंचायत व्दारा करवाये गये विकास कार्यो का अवलोकन किया। कलेक्टर ने ग्राम पंचायत सांडिया को आदर्श ग्राम पंचायत बनाने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश भी पंचायत सचिव एवं सरपंच प्रतिनिधि को दिए। इस मौके पर जिला पंचायत सीईओ श्री गुरूप्रसाद, एसडीएम श्री पवन बारिया, तहसीलदार श्री बी.के.मकवाना, पंचायत समन्व यक अधिकारी श्री गोपाल कृष्ण, परिहार एवं अन्यय अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर श्री दिनेश जैन ने ग्राम पंचायत सांडिया के पंचायत भवन परिसर में बगीचा निर्माण कार्य, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग मॉडल, कूडादान निर्माण, पौधारोपण कार्य, शमशान(शांतिधाम) विकास कार्य, नाला निर्माण कार्य का मौके पर निरीक्षण किया और ग्राम पंचायत व्दारा करवाये गये कार्यो की सराहना की। सरपंच प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर सी.सी.टी.व्हीप. कैमरे लगाये जाना प्रस्तावित है। साथ ही गांव में प्रमुख स्थानों पर हाईमास्क भी लगाये जावेंगे। गांव में पब्लिक अनाउंस सिस्टम भी लग चुका है। तालाब के सौंदर्यीकरण का कार्य भी जारी है। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में जितने भी शासकीय भवन स्थित है, उन्हें। राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जाये।

कलेक्टर श्री दिनेश जैन ने ग्राम पंचायत फूलपुरा में नव निर्मित कृषक सुविधा केंद्र भवन का निरीक्षण किया और कृषक उत्पादक संगठन के सदस्यो से चर्चा कर, उनके व्दारा प्रस्तावित गतिविधियों की जानकारी ली। किसानों ने एफपीओ को समर्थन मूल्य खरीदी केंद्र स्थापित करने की अनुमति प्रदान करने की भी मांग की। इस कृषक सुविधा केंद्र पर क्षेत्र के किसानों के लिए ट्रेक्टर व अन्य कृषि उपकरण व सामग्री किराये पर उपलब्ध करवाई जावेगी। कलेक्टर श्री जैन ने फूलपुरा में एस.बी.एम. पार्क, (स्वच्छ भारत मिशन पार्क) निर्माण के कार्य का भी अवलोकन किया। उन्होने इस पार्क में बनाये गये सामुदायिक शौचालय के मॉडल, सेग्रीगेशन शेड, एफ.एस.टी.सी. के मॉडल वर्मीकम्पोमस्ट पिट का भी अवलोकन किया। ग्राम पंचायत व्दारा करवाये गये कार्यो की कलेक्टर ने सराहना की।

श्रमिक को साईकिल वितरित:- कलेक्टर श्री दिनेश जैन व्दारा म.प्र.कर्मकार कल्याण मण्डल की योजना के तहत सांडिया के पंजीकृत श्रमिक अशोक प्रभुराम पुरोहित को श्रम विभाग की तरफ से साईकिल खरीदने के लिए प्रदान किए गऐ अनुदान से खरीदी गई साईकिल भी प्रदान की।

कलेक्टर श्री जैन ने किसान के खेत में जाकर की फसल की गिरदावरी:- कलेक्टर श्री दिनेश जैन ने ग्राम सांडियां के भ्रमण के दौरान बुधवार को ग्राम सांडियां में किसान देवप्रकाश तिवारी के खेत पर जाकर युवा किसान श्री मुकेश कुमार व्दारा की जा रही फसल की ऑनलाईन स्पाट गिरदावरी कार्य का जायजा लिया। कलेक्टर श्री जैन ने स्वयं मोबाईल पर किसान देवप्रकाश के खेत में खडी अलसी की फसल की खेत में जाकर स्वयं ऑनलाईन गिरदावरी की। युवा किसान मुकेश कुमार व्दारा गांव के सभी 1204 किसानों के खेतों पर जाकर फसल गिरदावरी का कार्य किया जा रहा है।

उड़ने से पूर्व हमें अपने पंखों की परीक्षा लेनी चाहिए ताकि हम आसमां में ज्यादा समय तक टिक पाये -सक्सेना

मंदसौर, 31 जनवरी गुरु एक्सप्रेस। उडने से पूर्व हमें अपने पंखों की परीक्षा लेनी चाहिए ताकि हम आसमां में ज्यादा समय तक टिक पाये।

यह बात हाईकोर्ट के सेवानिवृत्ति न्यायाधीश श्री गिरिराज जी सक्सेना ने मुख्य अतिथि के रूप में सरस्वती विहार शैक्षिक संस्थान में आयोजित समारोह में विद्यार्थियों को उद्बोधित करते हुए कहीं। समारोह के प्रारंभ में मुख्य अतिथि श्री सक्सेना, कार्यक्रम के विशिष्ठ अतिथि सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश श्री रघुवीर चुंडावत, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश श्री कैलाशचंद्र मानना, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री गुरचरण बग्गा, सरस्वती विहार शैक्षिक संस्थान की संचालन समिति भारतीय आदर्श शिक्षण समिति के अध्यक्ष श्री अशोक पारीख, संस्था प्रबंधक व समिति के सहसचिव श्री सुनील शर्मा, समिति कोषाध्यक्ष श्री राजदीप परवाल, समिति उपाध्यक्ष श्रीमती वर्तिका पारीक द्वारा ध्वजारोहण किया गया।

इसके पश्चात भैया बहिनों द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत संगीत प्रस्तुति, समता प्रदर्शन, घातक टीम प्रदर्शन, रोप मलखंभ जैसी कई जोश व उत्साह से परिपूर्ण प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम की अतिथियों द्वारा गत वर्ष के सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इसी श्रृंखला में विद्यालय रत्न बहिन यशस्वी उपाध्याय को भी मंच द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मंदसौर के जिला संघचालक श्री दशरथ सिंह झाला, शिक्षा महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. निशा महाराणा, सैनिक स्कूल व सीबीएसई की प्राचार्या डॉ. सरोज प्रसाद, एमपी बोर्ड विद्यालय के प्राचार्य महेश वमा, छात्रावास अधीक्षक श्री कमल किशोर गोठी, प्रधानाचार्य श्री प्रवीण मिश्रा, उप प्राचार्या सुश्री लक्ष्मी राठौड, समस्त भैया बहिन एवं आचार्य परिवार उपस्थित रहे।

भागवत सनातन धर्म का एक अध्यात्म दीप है-आचार्य दवे

झावल, 31 जनवरी गुरु एक्सप्रेस। ग्राम झावल में सात दिवसीय संगीतमय भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। कथा के प्रारंभ में कलश यात्रा का भव्य आयोजन हुआ। जिसमें मातृशक्ति कलश लेकर नृत्य करते हुए चल रही थी।

कलश यात्रा कथा स्थल पहुंची। जहां पोथी पूजन किया गया तथा भागवत प्रवक्ता आचार्य ओमप्रकाश दवे का स्वागत किया। भागवत कथा कहतेह आचार्य श्री दवे ने कहा कि भागवत सनातन धर्म का एक अध्यात्म दीप है। भागवत श्रवण मूल्य कर्मो का फल है। हमें अपने मौलिक, चिन्तन, मौलिक विचार एवं सनातन संस्कृति से जुडे रहना है। आपने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण मनुष्य जीवन को सार्थक बनाती है। जन्म तो हर प्राणी एवं मनुष्य लेता है लेकिन उसे अपने जीवन का अर्थ बोध नहीं होता है। बाल्यावस्था से लेकर मृत्यु तक वह सांसारिक गतिविधियों में ही लिप्त होकर इस अमूल्य जीवन को नश्वर बना देता है। श्रीमद् भागवत ऐसी कथा है जो जीवन के उद्देश्य एवं दिशा को दर्शाती है। इसलिए जहां भी भागवत होती है इसे सुनने मात्र से वहां का संपूर्ण क्षेत्र दुष्टप्रवृत्तियों से खत्म होकर सकारात्मक ऊर्जा से सशक्त हो जाता है।

आचार्य श्री दवे ने कहा कि श्रीकृष्ण का जन्म मनुष्य जीवन के उद्धार के लिए हुआ है। कंस ने उनके जन्म लेने को रोकने के लिए अथक प्रयास किए लेकिन सफल नहीं हो पाया। अंत में अपने पापों का घडा भरने पर श्रीकृष्ण के हाथों मरकर मोक्ष की प्राप्ति की। उन्होंने बताया मनुष्य जीवन सबसे उत्तम माना जाता है। इसी योनी में भगवान भी जन्म लेना चाहते हैं। जिससे वे अपने आराध्य ईश्वर की भक्ति कर सके। श्रीकृष्ण ने भागवत गीता के माध्यम से बुराई व सदाचार के बीच अंतर बताया। ईश्वर को धन दौलत व यज्ञों से कोई सरोकार नहीं है। वह तो केवल स्वच्छ मन से की गई आराधना के अधीन होता है। कथा श्रवण करने ग्राम झांवल सहित आसपास क्षेत्र के अनेक भक्तगण पहुंच रहे है। कथा 4 फरवरी तक प्रतिदिन दोप. 12 से 4 बजे तक हो रही है। आयोजन समिति ने सभी भक्तों से कथा में उपस्थित होकर धर्मलाभ लेने की अपील की है।

जिला अस्पताल में क्वालिटी एंश्योरेंस सर्टिफिकेट के प्रोटोकाल अनुरूप स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जायेगी-जैन

नीमच, 31 जनवरी गुरु एक्सप्रेस। जिला अस्पताल नीमच में केंद्र सरकार के क्वालिटी एंश्योरेंस सर्टिफिकेट के प्रोटोकाल के अनुरूप स्वास्थ्य सेवाएं व सुविधाएं उपलब्ध करवाई जायेगी। जिससे कि अस्पताल में मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। यह बात कलेक्टर श्री दिनेश जैन ने बुधवार को जिला अस्पताल नीमच के निरीक्षण के लिए स्वास्थ्य विभाग भोपाल से आई कायाकल्प टीम के डॉ.विवेक मिश्रा, एवं डॉ. सौरभ मण्डवारिया से चर्चा में कही। इस मौक पर जिला पंचायत सीईओ श्री गुरूप्रसाद, सिविल सर्जन डॉ.महेन्द्र पाटिल, डॉ.मनीष यादव व अन्यर चिकित्सकगण, स्वास्थ्य का स्टाफ उपस्थित था।

कलेक्टर श्री जैन ने बुधवार को जिला चिकित्सालय पहुंच कर, कायाकल्प टीम के सदस्यों से मुलाकात की और उन्हें जिले में स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों से अवगत कराया। कलेक्टर श्री जैन ने कायाकल्प टीम को अवगत कराया कि जिले में रक्तदान महाअभियान के तहत वर्ल्ड रिकार्ड हांसिल किया है। सभी मेडिकल स्टोर्स पर बी.पी.जांच का नि:शुल्क अभियान भी संचालित है। सशस्त्र सेना झण्डा दिवस पर 1.20 करोड की राशि संग्रहित कर रिकार्ड स्थापित किया गया है। टी.बी.मुक्त भारत अभियान के तहत 51 पंचायतें टी.बी.मुक्त घोषित कर दी गई है। जिलों को 2024 में टी.बी.मुक्त कर दिया जावेगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान जिले में 38 हजार टी.बी. मरीजों की जांच की गई है। पांच हजार से अधिक फूड बास्केट टी.बी. मरीजों को वितरित की गई है। फूड बास्केट वितरण का कार्य पंचायतों के माध्यम से निरंतर जारी है। कायाकल्प टीम के डॉ.विवेक मिश्रा ने अवगत कराया कि जिला चिकित्सालय नीमच में क्वालिटी एंश्योरेंस सर्टिफिकेट की गाईडलाईन प्रोटोकाल अनुसार स्वास्थ्य सेवाएं सुविधाएं उपलब्ध होती है, तो शासन व्दारा प्रति बेड के मान से दस हजार रूपये सालाना, इस तरह तीन सौ बेड के लिए 30 लाख रूपये की अतिरिक्त राशि स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए से उपलब्ध कराई जावेगी। प्रारंभ में कलेक्टर श्री दिनेश जैन ने कायाकल्प टीम के डॉ.विवेक मिश्रा एवं श्री सौरभ मण्डा वरिया को पगडी पहनाकर एवं पुष्प गुच्छ भेंटकर स्वॉगत किया।

पिता की सेवा से बड़ा कोई पुण्य धर्म नहीं होता है -पं.उपाध्याय

नीमच, 31 जनवरी गुरु एक्सप्रेस। बगीचा नंबर 10 क्षेत्रवासियों द्वारा क्षेत्र की सुख समृद्धि एवं सुख शांति की प्रार्थना के साथ सात दिवसीय शिव पुराण कथा आयोजित की गई। शिव पुराण के मध्य भागवताचार्य पंडित प्रमोद महाराज मनासा ने कहा कि जो व्यक्ति माता-पिता की सेवा करता है वह ईश्वर की सेवा के समान होती है। माता पिता की सेवा सबसे बडा कोई पुण्य धर्म नहीं होता है। माता-पिता की परिक्रमा को ही गणेश जी ने ब्रह्मांड की परिक्रमा माना था।तो संसार में प्रथम पूज्य गणेश जी के स्थान को प्राप्त किया था। माता-पिता की सेवा करने वाला गणपति के समान बुद्धिमान बनता है।उन्होंने कहा किओम नम: शिवाय का जाप करें तो जीवन में कल्याण होता है। उन्होंने कहा कि शिव की साधना करेंगे तो भक्त को शिव कृपा का फल अवश्य मिलेगा। उन्होंने कहा कि शिवरात्रि में शयन नहीं करना चाहिए रात्रि जागरण करना चाहिए। इससे पुण्य फल प्राप्त होता है। हम तपस्या करेंगे तो फल भी हमें ही मिलेगा। शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए इसके नियमों का पालन करना चाहिए।शिव की निर्मल भक्ति प्रेम का संदेश देती है।गणपति की लीलाएं माता-पिता के सम्मान का संस्कार सिखाती है।भक्ति में दिखावा नहीं प्रेम समर्पण होना चाहिए तभी जीवन में सफलता मिलती है।

पूर्व से स्वीकृत पासपोर्ट कार्यालय जल्द से जल्द शुरू करने हेतु शहर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष डॉ तोमर कलेक्टर मंदसौर को पत्र लिखा...

मंदसौर विधायक जैन से भी कार्यवाही का निवेदन किया

मंदसौर, 31 जनवरी गुरु एक्सप्रेस। विगत कई वर्षों से मन्दसौर में स्वीकृत पासपोर्ट कार्यालय प्रारंभ नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में कई बार नागरिकों व राजनैतिक कार्यकर्ताओं द्वारा जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों को पत्र लिखे गए लेकिन उसके बावजूद भी पासपोर्ट कार्यालय शुरू नहीं होने से क्षेत्र के नागरिकों को अनेक असुविधाओं का सामना करना पड रहा है। बुधवार को इस संबंध में शहर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष डॉ राघवेन्द्रसिंह तोमर ने मंदसौर कलेक्टर को पत्र लिखकर स्वीकृत पासपोर्ट कार्यालय को त्वरित कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द मंदसौर में शुरू करने की मांग की है।

डॉ तोमर ने पत्र की एक प्रति मंदसौर के विधायक श्री विपिन जी जैन को भेज कर उनसे भी इस संबंध में कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। मामले की जानकारी देते हुए डॉ तोमर ने बताया कि मंदसौर पासपोर्ट कार्यालय कई वर्षों से स्वीकृत हो चुका है पहले स्थान के अभाव में शुरू नहीं हो पा रहा था अब स्थान उपलब्ध होने के बाद भी कार्यालय शुरू होने में विलंब हो रहा है। जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों को चाहिए कि अभिलंब पासपोर्ट कार्यालय की शुरुआत हो ताकि मंदसौर जिले के नागरिकों को असुविधा से बचाया जा सके तथा उनके समय व धन की हानि से भी बचाया जा सके। पासपोर्ट कार्यालय मंदसौर में न होने के कारण मन्दसौर जिले के नागरिकों को अभी बाहर जाना पडता है,जिससे उनके समय व धन की हानि होती है। मंदसौर में पासपोर्ट कार्यालय प्रारंभ होने के पश्चात मंदसौर के नागरिकों को सुविधा मिलेगी।

व्यंग्य - सेवा शुल्क

किसी भी कार्यालय में काम करवाने के लिए पहले रिश्वत का चलन था किन्तु अब वे दिन लद गये अब कहीं भी रिश्वत नहीं ली जाती केवल सेवा शुल्क लिया जाता है और सेवा तो पवित्र मानी जाती है। कहीं आन लाइन काम है तो कहीं कहीं सर्वर डाउन हो जाता है या बंद हो जाता है लेकिन यदि उसकी सेवा कर दी जाए तो अर्ध रात्रि में भी चालू हो जाएगा। सेवा शुल्क कार्य के स्तर के अनुसार निर्धारित होता है चाहे नेताजी से सेवा लेना हो या किसी कार्यालय से , वैसे यह बात भी सही है कि जो मुफ्त की सेवा लेता है वह पाप का भागी होता है, सभी कथाकार भी यही कहते हैं , रोहन जैसा अडियल आदमी मैंने आज तक नहीं देखा, रोहन ने जैसे तैसे एक प्लाट खरीदा व निर्धारित सेवा शुल्क व फीस चुकाकर रजिस्ट्री कराई। उसके बाद नगर पालिका की नामांतरण शाखा में आवेदन लेकर गया तो बाबू ने कहा, ' ऐसे नहीं , ऐसे कागज लगाकर कल ले आना।' दूसरे दिन गया तो बाबूजी नहीं मिले । उसने सोचा दो दिन कमाई से गया । अत: अपने प्लाट खरीदी दलाल को सेवा शुल्क सहित आवेदन दे दिया। दूसरे दिन दलाल ने आवेदन जमा कर रसीद उसे लाकर दे दी और कहा तीन महीने बाद बैठक होगी उसके बाद जाकर तलाश कर लेना । उसने समाचार पत्रों में विज्ञप्तियां देखी , उसका नाम नहीं था। उसने बाबू से जाकर पूछा, ' बाबू ने कहा हां छूट गया होगा, दो महीने बाद बैठक होगी फिर तलाश कर लेना।' यह कहकर उसे टरका दिया। दो महीने बाद फिर गया बाबू ने कहा , ' 'आपकी फाइल पर सी एम ओ के दस्खत रह गये थे इसलिए फाइल चल नहीं पाई । ' वह हर महीने जाता थक गया । एक दिन उसने समाचार पत्र में पढा कि कलेक्टर ने चार्ज ले लिया और अनापत्ति वाले छूट गये सारे नामांतरण कर दिये । यह देख वह पन्द्रह दिन बाद अपने नामांतरण के लिए पहुंचा , ' बाबू ने कहा अभी फाइल उपर मंजिल से नहीं आई , अगले महीने आना । ' वह फिर गया बाबू नहीं मिला चपरासी ने कहा, ' बाबूजी सीएम ओ की मीटिंग में व्यस्त हैं आज नहीं आयेंगे,कल आना। ' ऐसे दो तीन हफ्ते फिर टल गये। दो बरस होने को आये नामांतरण कब मिलेगा यह सोच एक दिन बाबू के आफिस के बाहर बेंच पर अंगद की तरह जमकर बैठ गया । बाबू आया रोहन से कहा , ' चपरासी से कहो आपकी फाइल ढूंढ दे । ' चपरासी अछताता -पछताता गया अंदर बस्ते पर पडी फाइल लाकर बाबू को दी और बाबू ने अनमने मन से नामांकन प्राप्ति पर उसके हस्ताक्षर ले कागज देते हुए कहा , ' अरे भाई कुछ तो करो यों सूखे सूखे कहां जा रहे हो। '

रोहन बोला ,आवेदन के समय सब फिस चुका तो दी थी । ' बाबू बोला, ' वो दूसरे बाबू थे।'इतने में चपरासी रास्ता रोककर बोला भाई साहब मैं फाइल ढूंढकर लाया मेरा सेवा शुल्क तो दो । रोहन ने सौ की नोट उसके मुंह में ठूंसते हुए कहा, ' ले ये तुझे और तेरे बाबू को पचेगा नहीं। और चलता बना। चपरासी आंखें फाडकर खों खों करता रह गया ।' अरे भाई सेवा शुल्क देने का यह क्या तरीका है।

भगवती प्रसाद गेहलोत,
पिपलियामंडी

मंदसौर मंडी भाव

उपज	आवक बोरी में	न्यूनतम	अधिकतम
मक्का	103	2140	2262
उडद	34	5481	8615
सोयाबीन	2960	3590	4600
गैहु	2289	2300	3161
चना	26	5070	5481
मसुर	64	4747	5925
धनिया	225	4710	6850
लहसुन	11000	16001	29300
मैथी	603	4700	6611
अलसी	1290	4610	4910
सरसो	1450	4250	4821
तारामीरा	-	-	-
इसबगोल	26	9500	16000
प्याज	1962	280	1302
कलोंजी	28	13801	17281
डॉलर	00	00	00
तिल्ली	5	14761	14761
मटरसुखी	2	2800	2800
असालीया	209	6651	8881

जनजातीय युवाओं के लिये स्वरोजगार व विकास की तीन नई योजनाएं

भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना में 22.10 करोड़ रूपये और टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना में 2.66 करोड़ रूपये वित्तीय सहायता वितरीत

मंदसौर, 31 जनवरी गुरु एक्सप्रेस। जनजातीय कार्य विभाग के अधीन मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम द्वारा तीन नई वित्तीय सहायता योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इनमें से भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना और टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के माध्यम से जनजातीय वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उनके समग्र कल्याण के प्रयास किये जा रहे हैं। मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम को 'भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना' में 31 जनवरी 2024 तक कुल 5 हजार 523 आवेदन मिले। इनमें से बैंकों द्वारा 716 आवेदन मंजूर कर 561 पात्र हितग्राहियों को 22 करोड़ 10 लाख 64 हजार 895 रूपये वित्तीय सहायता वितरित की जा चुकी है। केवल 155 प्रकरण वित्त सहायता वितरण की अंतिम प्रक्रिया में हैं। इस योजना में जनजातीय युवाओं को विनिर्माण गतिविधियों के लिए एक लाख से 50 लाख रूपये तथा सेवा व व्यवसाय गतिविधियों के लिए एक लाख से 25 लाख रूपये तक की वित्तीय सहायता बैंकों के माध्यम से दी जाती है। बैंक ऋण पर अधिकतम सात वर्षों के लिए पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान एवं बैंक गारंटी का भुगतान राज्य शासन द्वारा किया जाता है।

'टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना' में निगम को 31 जनवरी 2024 तक कुल 6 हजार 11 आवेदन मिले। बैंकों द्वारा 699 आवेदन मंजूर कर 490 पात्र हितग्राहियों को दो करोड़ 66 लाख 5 हजार 165 रूपये वितरित किये जा चुके हैं। सिर्फ 209 प्रकरण अंतिम निराकरण के लिए लंबित हैं। इस योजना में जनजातीय युवाओं को 10 हजार से एक लाख रूपए तक की स्व-रोज़गार परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता बैंकों के माध्यम से दी जाती है। बैंक ऋण पर अधिकतम पाँच वर्षों के लिए सात प्रतिशत ब्याज अनुदान एवं बैंक गारंटी राज्य शासन द्वारा दी जाती है। इन दोनों योजनाओं से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं लाभ प्राप्ति के लिए 'समस्त पोर्टल' https://samast.mponline.gov.in पर लॉग-इन कर या जिलास्तर पर सहायक आयुक्त/जिला संयोजक जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। इसी प्रकार 'मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना' में जनजातीय युवाओं को आजीविका, स्वरोजगार एवं नवाचार से संबंधित सामुदायिक अधोसंरचना निर्माण तथा इससे जुड़ी अन्य गतिविधियों की दो करोड़ रूपये तक की ऐसी परियोजनाएं, जिनका क्रियान्वयन लाईन विभागों की किसी प्रचलित योजना/परियोजना में किया जाना संभव नहीं हो, उसका शत-प्रतिशत शासन अनुदान से वित्त पोषण किया जाता है। इस योजना का क्रियान्वयन लाईन विभागों/कलेक्टर के माध्यम से किया जा रहा है।

मामला गैंगरेप पीडिता एवं उसके परिवार को राहत खर्च राशि का...

विधायक जैन ने मुख्यमंत्री यादव को पत्र लिखकर पूर्व मुख्यमंत्री की घोषणा को अमलीजामा पहनाने का आग्रह किया

मंदसौर, 31 जनवरी गुरु एक्सप्रेस। वर्ष 2018 में मंदसौर में मानवता को शर्मसार करने वाले बालिका गैंगरेप के मामले में पीडिता एवं उसके परिवार को राहत हेतु जो घोषणाये मध्यप्रदेश सरकार के तत्कालिन मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चैहान द्वारा की गयी थी उस पर अमल नही होने के मामले में मंदसौर विधायक विपिन जैन ने मध्यप्रदेश शासन के नवागत मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव को पत्र लिखकर मानवीय पहलु से जुडे राहत मामले में पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चैहान की घोषणा के अनुरूप अमलीजामा पहनाने का आग्रह किया है।

विधायक श्री विपिन जैन ने मिडीया द्वारा गैंगरेप पीडिता एवं उसकी बहन की स्कूल फिस एवं अन्य खर्च की राशि बकाया होने एवं स्कूल प्रबंधन द्वारा 14 लाख रूपये की राशि का नोटिस का मामला संज्ञान में लाये जाने के उपरांत मध्यप्रदेश शासन के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव को पत्र के माध्यम से मंदसौर की गैंगरेप पीडिता मासुम बालिका के लिये तत्कालिन मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चैहान द्वारा की गयी घोषणा पर पूर्ण करने की अपील की है। श्री जैन ने कहा कि मासुम बालिका एवं उसके परिवार के साथ घटी घटना मानवीय संवेदना से जुडा विषय है जिस पर राजनिति कदापि उचित नही है किन्तु यह बताते हुये अत्यंत असहज महसुस हो रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्रीजी की हर घोषणा की तरह यह घोषणा भी अधुरी रह गयी है। पीडिता के पिता को स्कूल प्रबंधन द्वारा 14 लाख की राशि जमा करने का नोटिस थमाया गया है जो कही न कही मानवीयता को शर्मसार करने वाला प्रसंग निर्मित होता दिख रहा है। श्री विधायक श्री जैन ने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव से कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्रीजी द्वारा ली गयी जिम्मेदारी को सरकार ने गंभीरता से नही लिया है, हो सकता है कि इसका ठिकरा अधिकारियो पर फोडा जाये किन्तु मेरा आपसे आग्रह है कि इस संबंध में पीडिता एवं उसके परिवार के लिये लंबित घोषणाओ पर आवश्यक जांच कर पीडिता एवं उसके परिवार के अन्य सदस्य के लिये अन्य खर्च राशि जमा करवाने के लिये कदम उठाया जाना चाहिये। उन्होनें मुख्यमंत्री महोदय से तत्काल पीडिता के परिवार के लिये शिक्षा एवं अन्य मद में खर्च राशि जमा करने के निर्देश सक्षम अधिकारियो को देने का आग्रह किया है।

सामाजिक न्याय, धार्मिक सौहार्द बंधुत्व के लिए निकली संविधान यात्रा, महात्मा गांधी को किया याद

मनासा, 31 जनवरी गुरु एक्सप्रेस। क्षेत्र में गांधी विचार को लेकर काम कर रही संस्था 'गांधी 150' गांधी विचार मंच द्वारा 30 जनवरी गांधी पुण्यतिथि पर तहसील मनासा में अनेकों स्थानों पर संविधान एवम गांधी विचार पर आयोजन किए गए। इन आयोजनों में संविधान की प्रस्तावना का वितरण, वाचन एवम शपथ ली गई साथ ही गांधी के सत्य अहिंसा और स्वराज्य की अवधारणा पर लोगों के बीच संवाद किया गया। इसकी शुरुवात में गांव बरथून गांधी प्रतिमा पर पुष्पांजलि के पश्चात सर्वधर्म प्रार्थना सभा गांव के लोगों ने की। गांव के पूर्व सरपंच दिनबंधु बैरागी द्वारा उनके कार्यकाल में गांधी प्रतिमा स्थापित करने के लिए स्मृति चिन्ह एवम हम भारत के लोग पुस्तक भेंट कर सम्मानित किया गया। साथ ही जिन जिन महानुभावों ने गांधी चबूतरा प्रतिमा के लिए अपनी जमीन दान की उनका भी सम्मान किया गया। देश के अनेकों आंदोलन में भूमिका निभाने वाले खुदाई खिदमतगार दिल्ली से संबंधित सोशल एक्टिविस्ट कृपाल मंडलोई ने संविधान यात्रा के उद्देश्य, गांधी विचार आज की जरूरत पर प्रकाश डाला। इस प्रार्थना सभा को मनासा के वरिष्ठ समाजसेवी महेश मालिक, मानवाधिकार आयोग के पूर्व सदस्य व प्रसिद्ध रंगकर्मी विजय बैरागी अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक गुलाब सिंह चंद्रावत, सामाजिक कार्यकर्ता महेंद्र उपाध्याय ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन गांधी 150 के कार्यक्रम संयोजक महेश नंदवाना ने किया। इसके पश्चात संविधान यात्रा प्रारंभ हुई जो गांव महागढ पंहुची। महागढ में मुख्य बाजार व चौराहे पर संविधान की प्रस्तावना का वितरण वाचन किया गया। इसके पश्चात् मनासा कारगिल चौराहा स्थित अन्नपूर्णा मंदिर परिसर में कार्यकर्म का अयोजन हुआ यहां नौजवान सभा के प्रतिनिधि यश लोहार ने संविधान की शपथ दिलाई। संविधान यात्रा का गांव भाटखेड़ी में शारदा विद्या निकेतन, विद्यासागर स्कूल के बच्चों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया यहां बच्चों के बीच कविताओं, गीतों के माध्यम से संविधान व गांधी विचार पर संवाद हुआ इस अवसर पर इन संस्थाओं के प्रमुख क्रमश: कमलेश पाटीदार एवं रामचंद्र पाटीदार ने इस आयोजन के लिए आभार व्यक्त किया। संविधान यात्रा के गांव परदा पहुंचने पर वह स्थानीय लोगों के बीच प्रस्तावना वितरण वी वाचन किया गया। यात्रा का समापन आदिवासी बहुल गांव खेलड़ी में हुआ स्थानीय लोगों और बच्चों के बीच सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ यहां देश के प्रसिद्ध आर्टिस्ट व बीबीसी लंदन से पुरस्कृत मदन राठौर ने इस यात्रा की अगवानी की। इसके पश्चात पगत में संगत स्नेह भोज के साथ संविधान यात्रा का समापन हुआ। विश्व बंधुत्व आर्थिक सामाजिक न्याय व संविधान के उद्देश्यों, गांधी विचार को लेकर निकली इस यात्रा में क्षेत्र के सामाजिक, सांस्कृतिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया इसमें शिक्षाविद श्याम शालवी, दलित नेता जगदीश मालवीय, समरथ चोरडिया, नितेश मालवीय, अल्पसंख्यक समुदाय के नेता समाजसेवी अयूब खान, ब्राह्मण समाज के अनिल पुरोहित, गांधीवादी युवा गौरव तिवारी, नौजवान सभा नीमच के यश लोहार, ललित माहेश्वरी, प्रेमसिंग रावत, हरिदास बैरागी कुकडेश्वर, नीमच के युवा मोर्चा के दिनेश लोहार, निखिल चौहान, साहिल शेख उपस्थित रहे।

स्व सहायता समूह के जरिए आधी आबादी से संपर्क करेगी भाजपा

शक्ति वंदन महिला स्व सहायता समूह एवं एनजीओ संपर्क अभियान की कार्यशाला भाजपा कार्यालय पर संपन्न

मंदसौर, 31 जनवरी गुरु एक्सप्रेस। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जिला शक्ति वंदन महिला स्वयं सहायता समूह ग्रुप एवं एनजीओ सपर्क अभियान की जिला कार्यशाला, भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश प्रभारी राज्यसभा सांसद सुश्री कविता पाटीदार, भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष माया नारोलिया, प्रदेश संयोजक लता वानखेडे के निर्देशानुसार दिनांक 31 जनवरी 2024 बुधवार को दोपहर 01 बजे भारतीय जनता पार्टी मंदसौर जिला कार्यालय में आयोजित हुई! सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत प्रमुख वक्ता और जिला टीम द्वारा राज माता सिंधिया जी की तस्वीर पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया! जिसमें भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष व गंजबासोदा (जिला विदिशा) नगरपालिका अध्यक्ष वक्ता शशि यादव, भाजपा जिलाध्यक्ष नानालाल अटोलिया, कार्यक्रम जिला प्रभारी एंव भाजपा जिला महामंत्री राजेश दीक्षित, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुषमा आर्य, भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष निर्मला गुप्ता की गरिमामय उपस्थिति में कार्यशाला संपन्न हुई।

कार्यशाला शुरू होने के बाद सर्वप्रथम भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष द्वारा शक्ति वंदन कार्यशाला की रूपरेखा की जानकारी के साथ महिला स्व सहायता समुह ग्रुप एवं एनजीओ संपर्क अभियान की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत कर सभी कार्यकर्ता को 61% वोट का लक्ष्म पूरा कर भाजपा सरकार को एक बार फिर विजय बनाना हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष नाना लाल जी अटोलिया ने सभी भाजपा मंडल और महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष के साथ बनाई गई टीम के कार्यकर्ताओं को एनजीओ से जुडे महिला स्व सहायता समुह की बहनो से जुड़ कर उन्हें भारत सरकार की स्व सहायता के साथ जुडी योजनाओं से मजबूती देने का आग्रह किया गया, जिससे भाजपा के 60% वोट पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और केंद्र मे फिर एक बार मोदी सरकार भाजपा अपने कार्यो के माध्यम से परचम लहराएगा। महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष व गंजबासोदा (जिला विदिशा) नगरपालिका अध्यक्ष शशि यादव ने अपने वक्तव्य में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भाजपा सरकार द्वारा आज नारी शक्ति वंदन बिल बना है जिसमें 33% बहने आने वाले लोकसभा चुनावों मे अपनी सहभागिता बहुत ही बड़ी संख्या मे निभाएगी। भाजपा सरकार द्वारा महिलाओं के हित में चलाई गई योजनाओं की जानकारी देते हुवे कहा की महिलाओं को हर क्षेत्र में आरक्षण देने का काम मोदी सरकार ने किया है 2026 में विधानसभाओं और लोकसभा में भी 33 प्रतिशत महिलाएं चुनकर जाएगी। स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाए आत्मनिर्भर बनकर समूह के माध्यम से कार्य कर रही है। भाजपा की सरकार इन समूह के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर और लखपति बनाने का कार्य कर रही है, महिलाओं को सक्षम बनाने का काम मोदी जी ने किया है अब आपका भी फर्ज है की आप 2024 में मोदी जी की सरकार बनाने में अपने अपने गांव में जुट जाए महिलाओं के अपार समर्थन से मध्यप्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है अब मोदी जी की भी सरकार बनवाने में जुट जाए। जिला कार्यशाला में भाजपा, मोर्चा पदाधिकारियों कार्यकर्ता सहित बड़ी संख्या में जिले भर की स्व सहायता समूह की महिलाए मोजूद थी। कार्यशाला का संचालन महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष सुनीता गुजरिया ने किया एवं आभार महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष रानू भावसार ने माना। कार्यशाला में भाजपा मंडल अध्यक्ष, भाजपा महिला मोर्चा जिला पदाधिकारी, मोर्चा मंडल अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष, पार्षदगण, सरपंच बहने आदि अपेक्षित श्रेणी की मातृशक्ति बंधुवर कार्यशाला में उपस्थित रहें।

महावीर पुस्तकालय ने ऊनी स्वेटर बाटे

मंदसौर, 31 जनवरी गुरु एक्सप्रेस। श्री कमलमुनि ने सिंदपन गांव में विशाल गौशाला के निर्माण व संचालन का आदर्श कायम किया है।

महावीर पुस्तकालय एवं वस्त्र वितरण संस्था ने शासकीय प्राथमिक विद्यालय सिंदपन में गरीब विद्यार्थियों को नये गरम कपड़े एवं स्वेटर वितरण किये। पूर्व वर्षो में भी 2 बार ऐसा कार्यक्रम हुआ। समाजसेवक श्री अशोक नलवाया एवं पूर्व सेवानिवृत्त श्री शाकीर एहमद ने सिंदपन के स्कूल में जाकर विद्यार्थियो को स्वेटर पहनाये। सभी शिक्षकों ने पुण्य कमाया। सिंदपन क्षेत्र के 2 बुजुर्गो को गरम कोट भेंट किये गये। समारोह में सभी उपस्थित शाला प्रभारी अनिल पाटीदार, शिक्षक सुधा राठौड, सपना चंदेल, अनिल पुरोहित, दिनेश अड़ावदिया, तिजा प्रजापति, रानू शक्तावत आदि ने सहयोग करके आनन्द की अनुभूति प्रदान की। महावीर पुस्तकालय वस्त्र वितरण संस्था शासकीय ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में स्वेटर, कोट व अन्य सामग्री वितरण हेतु तत्पर है। ग्रामीण गरीब एवं विद्यार्थियों को उनके विद्यालयों में पहुंचकर सेवा दी जा रही है। सम्पूर्ण संसदीय क्षेत्र के प्रमुख गुरूजी महावीर पुस्तकालय मंदसौर से सम्पर्क कर बच्चों की मदद करें। शिक्षा विभाग का सराहनीय मार्गदर्शन सतत चालू है। समिति सबका आभार मानती है। संस्था का पता है कोठारी नगर संजीत नाका मंदसौर मो.नं. 7974413252 है।

प्रदेश में श्रवण बाधित विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के लिये सांकेतिक भाषा की सुविधा

राज्य शिक्षा केन्द्र ने जिला कलेक्टर को लिखा पत्र

मंदसौर, 31 जनवरी गुरु एक्सप्रेस। प्रदेश में श्रवण बाधित विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की सुविधा के लिये आधारभूत कौशल कोर्स तैयार किया गया है। यह कोर्स 30 से 40 घंटे का भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र ने ऑनलाइन तैयार किया है। श्रवण बाधित विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को यह कोर्स प्रशिक्षण केन्द्र की वेबसाइट www.islrtc.nic.in[a, यू-ट्यूब चेनल की लिंक पर तथा क्यू-आर कोड से डाउनलोड किया जा सकता है। जिला शिक्षा, जनपद और जनशिक्षा केन्द्रों के माध्यम से सभी स्कूलों में यह कोर्स बच्चों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिससे उन्हें अध्ययन में सुविधा हो सके। इस संबंध में विस्तृत जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं जिला परियोजना समन्वयक राज्य शिक्षा केन्द्र कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं।

कक्षा 5 एवं 8 की वार्षिक परीक्षा के तृतीय भाषा के निर्देश–दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कक्षा 5 व 8 के दृष्टिबाधित छात्रों के लिये गणित विषय के स्थान पर संगीत विषय का विकल्प चयन करने का प्रावधान है। राज्य शिक्षा केन्द्र ने परीक्षा सत्र 2023-24 में कक्षा 5 एवं 8 की वार्षिक परीक्षा में तृतीय भाषा के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश जारी किये हैं। तृतीय भाषा अशासकीय शालाओं में मांग के अनुसार पंजाबी, गुजराती, उड़िया और संस्कृत है। कक्षा 8 में तृतीय भाषा के रूप में पंजाबी, गुजराती और उड़िया भाषा एवं राजगढ़ व बुरहानपुर जिलों में जिलों के अशासकीय विद्यालयों में कक्षा 5 में शालाओं की मांग के क्रम में अतिरिक्त भाषा के रूप में संस्कृत विषय का बच्चों को अध्ययन कराया गया है। राज्य शिक्षा केन्द्र में इन विषयों के प्रश्न पत्र डाईट स्तर पर निर्मित कराये जाने के संबंध में निर्देश दिये हैं। निर्देशों में कहा गया है कि जिले में दर्ज इन विषयों के बच्चों की वास्तविक संख्या के अनुसार प्रश्न पत्रों का निर्माण पूरी गोपनीयता के साथ समय-सीमा में किया जाए। इसका उत्तरदायित्व संबंधित जिला परियोजना समन्वयक का रहेगा।

जिले में नवीन उद्योग स्थापित करने के लिए पर्याप्त जमीन एवं भूखण्ड उपलब्ध है-जैन

कलेक्टर ने उद्योगपतियों से किया जिले में औद्योगिक ईकाईयां स्थापित करने का आव्हान

नीमच, 31 जनवरी गुरु एक्सप्रेस। जिले में औद्योगिक क्षेत्र झांझरवाडा, चेनपुरा, बामनबर्डी, जाट, जनकपुर, दुधवा, दारू, सगराना सहित अन्य, राज्य स्तरीय औद्योगिक कलस्टर में नवीन उद्योग स्थापित करने के लिए पर्याप्त, संख्या में भूखण्ड् एवं जमीन उपलब्ध है। उद्योगपति नवीन उद्योग जिले में स्थापित करने के लिए आगे आए, शासन व्दारा उन्हें हर सम्भव सहयोग एवं सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।

यह बात कलेक्टर श्री दिनेश जैन ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष नीमच में बुधवार को आयोजित जिला स्तरीय उद्योग संवर्धन समिति एवं जिला स्तरीय निर्यात संवंधन समिति की बैठक में उपस्थित जिले के उद्योगपतियों से चर्चा करते हुए कही। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री गुरूप्रसाद, महाप्रबंधक उद्योग, जिला अधिकारी एवं बडी संख्या में जिले के उद्योगपति एवं व्यापारी उपस्थित थे। महाप्रबंधक उद्योग नीमच ने बैठक में उद्योगपतियों को जिलों में विकसित किए जा रहे सात औद्योगिक कलस्ट्रों के बारे में जानकारी देते हुए इन कलस्टरों में नवीन उद्योगो की स्थापना के लिए हुए अनुबंधो की जानकारी दी। बैठक में बताया गया कि केसरपुरा, सगराना, दारू, दुधवा एवं बामनबर्डी में नवीन औद्योगिक कलस्टर के लिए जमीन चिन्हित कर कलस्टर का विकास किया जा रहा है। चेनपुरा, बामनबर्डी में 50 हेक्टेयर जमीन पर कलस्टर का विकास किया जा रहा है। बैठक में एमएसएमई विभाग और औद्योगिक विकास निगम के पास नवीन उद्योगो के लिए उपलब्ध भूखण्डों, जमीन के बारे में भी विस्तार से बताया गया। बैठक में कलेक्टर श्री जैन ने जिले से निर्यात की सम्भावनाओं पर भी उद्योगपतियों से विस्तार से चर्चा की।

दिव्यांगजनों के लिए रोजगार मेला लगाएंगे:– बैठक में कलेक्टर श्री दिनेश जैन ने कहा कि नीमच जिले में दिव्यांगजनों को विभिन्न उद्योगो में रोजगार उपलब्धं कराने के लिए दिव्यांगजन रोजगार मेला आयोजित किया जावेगा। कलेक्टर श्री जैन ने कहा कि दिव्यांगजनों की सूची कलेक्टोरेट में उपलब्ध है, यह सूची उद्योगपतियों को शेयर की जा रही है। उद्योगपति अपने उद्योगो में आवश्यकता के अनुरूप रोजगार के लिए दिव्यांगजनों को चिन्हित करे और रोजगार मेले में उपस्थित होकर, दिव्यांगजनों को उनकी योग्यता, स्कील्ड के अनुरूप रोजगार उपलब्ध करवाये। बैठक में उद्योगपतियों, व्योपारियों ने भी अपने महत्विपूर्ण सुझाव दिए।

विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक 3 को

नीमच, 31 जनवरी गुरु एक्सप्रेस। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक 3 फरवरी 2024 को प्रात: 9.30 बजे कलेक्टर सभाकक्ष जिला नीमच में सांसद श्री सुधीर गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। बैठक में जल निगम के कार्यों र्की समीक्षा, सोलर, पवन उर्जा, खिमला प्रोजेक्ट की समीक्षा, आबकारी विभाग की समीक्षा, (पुलिस विभाग के साथ) जल संसाधन विभाग की समीक्षा, खनिज विभाग के कार्यो र्की समीक्षा, पीआईयू के कार्यो की समीक्षा, लोक निर्माण विभाग एवं सेतु विकास निगम की समीक्षा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की समीक्षा एवं जिला पंचायत की समीक्षा एवं आगामी कार्ययोजना पर चर्चा की जावेगी। जिला पंचायत सीईओ श्री गुरूप्रसाद ने सभी जिला अधिकारियों को बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए है। उन्होयने समिति के सभी सदस्यों से भी बैठक में उपस्थित होने का आगृह किया है।

शून्य परीक्षा परिणाम वाले 54 स्कूलों के संस्थात प्रमुखों को नोटिस जारी

नीमच, 31 जनवरी गुरु एक्सप्रेस। जिला पंचायत सीईओ श्री गुरूप्रसाद के निर्देशानुसार कक्षा 5वीं व 8वी के वार्षिक परीक्षा परिणाम सत्र 2022-23 में शून्य परीक्षा परिणाम वाली विकासखण्ड जावद की 24, मनासा की 14 एवं नीमच की 16 शालाओं इस प्रकार तीनों विकासखण्ड की कुल 54 प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के संस्था प्रधानों को कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर किए गए है। उक्त जानकारी देते हुए डिप्टी कलेक्टार सुश्री किरण आंजना ने संबंधित संस्थाए प्रधानों को दो दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया है।

*** नाम परिवर्तन सूचना ***

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं निखिल खरे पिता शंकरलाल खरे के ड्रायविंग लायसेंस में मेरे सरनेम की स्पेलिंग में KHREY त्रुटिपूर्ण दर्ज है। जबकि आधार कार्ड में मेरा नाम सही है जिसमें मेरे सरनेम की स्पेलिंग KHARE है अत: मेरे सही नाम NIKHIL KHARE S/o Shankarlal KHARE से जाना एवं पहचाना जाए।

**** भवदीय ****

निखिल खरे पिता शंकरलाल खरे

इंद्रा कालोनी, पद्मावति रिसोर्ट के सामने गली नं. 3, मंदसौर

कार्यालय नगर परिषद पिपलियामंडी, जिला-मंदसौर (म.प्र.)

E-mail-cmopipliyamandi@mpurban.gov.in Phone No-07424-241071

क्रमांक-116,117, 118, 119,120/ई-निविदा/2024, पिपलियामंडी, दिनांक 29.01.2024

***** ई-निविदा आमंत्रण सूचना *****

निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाईन (Online) निविदा आमंत्रित की जाती है। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाईट https://mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

जा.क्रं.	ऑनलाईन टेण्डर नं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	समयावधि	टेण्डर क्रय की अंतिम तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
116/29.01.2024	2024_UAD_328725_1 प्रथम निविदा	वर्ष 2024-25 में जलप्रदाय योजनांतर्गत केमिकल ऐलम ग्रेड-1 एवं नागदा ग्रेसिम का ब्लिचिंग पाउडर क्रय संबंधी	20,00,000	15,000	2000	31 मार्च 2025 तक	29.02.2024
117/29.01.2024	2024_UAD_328744_1 प्रथम निविदा	वर्ष 2024-25 में विभागीय निर्माण कार्यों के लिए सामग्री क्रय संबंधी	20,00,000	15,000	2000	31 मार्च 2025 तक	29.02.2024
118/29.01.2024	2024_UAD_328845_1 प्रथम निविदा	वर्ष 2024-25 में स्वच्छता शाखा अंतर्गत सामग्री क्रय संबंधी	20,00,000	15,000	2000	31 मार्च 2025 तक	29.02.2024
119/29.01.2024	2024_UAD_328854_1 प्रथम निविदा	वर्ष 2024-25 में नगर की स्ट्रीट लाईट व्यवस्था अंतर्गत सामग्री क्रय संबंधी	20,00,000	15,000	2000	31 मार्च 2025 तक	29.02.2024
120/29.01.2024	2024_UAD_328862_1 प्रथम निविदा	वर्ष 2024-25 में जल प्रदाय योजनांतर्गत सामग्री क्रय संबंधी	20,00,000	15,000	2000	31 मार्च 2025 तक	29.02.2024

1.- निविदा दर ऑनलाईन प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक - 01.03.2024

2.- मूल दस्तावेज (फिजिकल) प्रस्तुत करने की दिनांक - 01.03.2024, प्रातः 11.00 बजे तक

नोट-(1) विस्तृत निविदा एवं अन्य दस्तावेज देखने एवं डाउनलोड करने के लिए https://mptenders.gov.in वेबसाईड पर सुविधा उपलब्ध है। अधिक जानकारी कार्यालय नगर परिषद पिपलियामंडी में देखी जा सकती है। (2) निविदा डाउनलोड करने के पूर्व निविदाकार निकाय में उपलब्ध शर्तों का अवलोकन करने के पश्चात ही टेण्डर क्रय करें। (3) निविदा में यदि कोई संशोधन होता है तो वह ऑनलाईन पोर्टल पर प्रदर्शित होगा। उसके लिए पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं कराया जावेगा। (4) शासन निर्देशानुसार जी.एस.टी. की समस्त शर्ते लागू होगी।

प्रमोद जैन, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद पिपलियामंडी

भारतसिंह सोनगरा, उपाध्यक्ष, नगर परिषद पिपलियामंडी

श्रीमती इंदिरा-सुनील देवदिया, अध्यक्ष, नगर परिषद पिपलियामंडी

स्वत्वाधिकारी, सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक आशुतोष नवाल के लिए गुरु मीडिया एण्ड इंटरटेनमेन्ट कम्पनी, शक्ति नगर मन्दसौर से मुद्रित एवं 77 लक्ष्मीनगर, वेदान्त विहार मन्दसौर से प्रकाशित। (हर प्रकार के विवाद का न्याय क्षेत्र मन्दसौर रहेगा) संपादक– आशुतोष नवाल RNI-MPHIN2006/20356
समाचार पत्र में छपे विज्ञापनों के लिए समाचार पत्र उत्तरादायी नहीं है एवं विज्ञापनो में प्रकाशित विचार विज्ञापनदाता की निजी राय है। इससे समाचार पत्र का कोई संबंध नहीं है। फोन 495831, मो. 9425105927,28 ashugurumds@gmail.com, ashu_guru2@yahoo.co.in